



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 1990/ज्येष्ठ 21, 1912

No. 139]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 1990/JYAISTHA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय
(पर्यावरण, वन तथा बन्धुत्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जून, 1990

सं. 1-4-90 एम.एम.-1:—विनांक 7 मई, 1985 के संकल्प सं. 7-22/85-वानिकी (पी) द्वारा राष्ट्रीय पर्ती भूमि विकास बोर्ड की गई थी। विनांक 1-4-90 के संकल्प संख्या 1-8/89-टी.एम.ए. द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड, पर्ती भूमि विकास कार्यश्रम की आयोजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में जन-सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने तथा ग्रन्ति-विषय समन्वय स्थापित करने के लिये मिशन का दृष्टिकोण अपनाएंगा।

2. तब्दील, राष्ट्रीय पर्ती भूमि विकास बोर्ड के गठन और उसकी भूमिका और कार्यों में तत्काल निम्न-लिखित परिवर्तन किये जाते हैं:—

गठन

क. पद्धति सदस्य :

- (1) केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री —ग्रध्यक्ष
- (2) केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री—उपग्रध्यक्ष
- (3) सदस्य, योजना आयोग, पर्यावरण कार्यभारी—सदस्य
- (4-8) निम्नलिखित विभागों में भारत सरकार के सचिव:—
- कृषि और सहकारिता —सदस्य
- ग्रामीण विकास —सदस्य
- कृषि अनुसंधान और शिक्षा —सदस्य
- व्यवस्था —सदस्य (वित्त)
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी —सदस्य
- (9) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड —सदस्य
- (10) वन महानिरीक्षक, भारत सरकार —सदस्य
- (11) ग्रध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक —सदस्य

क्र. नामित सदस्य :—

- (12-13) संसद सदस्य (नोंस मता और राज्य सभा प्रत्येक से एक-एक) —सदस्य
- (14-18) परती भूमि विकास और उसमें संबंधित कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं, आदि के प्रतिनिधि (5 से अधिक नहीं) (अध्यक्ष डारा प्रत्येक वर्ष नामित किये जायेंगे)
- (19-21) तीन राज्यों के मध्य सचिव (अध्यक्ष —सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किये जायेंगे)
- ग. सदस्य सचिव :—
- (22) सचिव (पर्यावरण और वन) —सदस्य सचिव

भूमिका और कार्य :—

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड देश में भूमि के निकुञ्जकरण को ग्रहने और उसे सतत उपयोग के लिये तैयार करने उपलब्ध बायोमास में वृद्धि करने विशेषण. ईधन लकड़ी, चारा और बनोपज के संदर्भ में और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने पर आधारित परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिये मुख्यतः उत्तरदायी होगा। बाइं, परती भूमि विकास कार्यक्रम की आयोजना तैयार करने तथा उसके कार्यविन्यास में जन-सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने तथा अन्तर्विषय समन्वय स्थापित करने के लिये मिशन का दृष्टिकोण अपनाएगा। इसके लिये बोर्ड :

- (1) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के संस्थान में देश में परती भूमि के सतत उपयोग के प्रबंध विकास के लिये एक संदर्भ योजना तैयार करेगा।
- (2) परती भूमि का पता लगाया, एक शिवसनीव आंकड़ा आधार तैयार करेगा और परती भूमि विकास कार्यक्रम हेतु अपेक्षित संसाधन और महायता उपलब्ध किये जाने के लिये केन्द्र और राज्य के संबंधित विभागों/एजेंसियों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में सोगों की ईधन लकड़ी, चारे, और बनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लागत प्रभावी रूप से सुध्यवस्थित आयोजना तैयार करने और उसके कार्यविन्यास के माध्यम से एकीकृत परती भूमि विकास हेतु एक कार्य प्रणाली तैयार करेगा।
- (4) पारिस्थितिकीय सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों की ईधन लकड़ी, चारे और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्राकृतिक पुनरुत्थान अथवा

समुचित मध्यस्थिता करके देश का हरा-भरा बनायेगा।

- (5) बन ज्ञेत्रों पर पड़ रहे द्वाष को कम करने यार उपयोग व विषणु की जहरतों की पूर्ति के लिये गैर-वन ज्ञेत्रों और निजी परती भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारे और इमारती लकड़ी का वृक्षारोपण करेगा।
- (6) परती भूमि के विकास हेतु नई और समुचित प्रौद्योगिकियों के प्रमार के लिये अत्यंता को प्रायोजित करेगा और अनुसंधान के परिणामों का विस्तार करेगा।
- (7) स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य के महायोग से परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिये जन-जागरूकता पैदा करेगा और एक जन-आंदोलन तैयार करने में मद्दत करेगा तथा मामूलायिक/मार्वर्जनिक भूमि व अन्य इमी प्रवाह के निकुञ्ज गामुदायिक सम्पत्ति संसाधनों में भारींदारी और उनके सतत प्रबंध को बढ़ावा देगा।
- (8) सुध्यवस्थित रूप में और लागत प्रभावी तरीके में भूमि की किस्म को उन्नत बनाने के लिये परती भूमि विकास, बनीकरण, वृक्षारोपण मृदा और नभी संरक्षण आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिये कार्य-योजनाओं का समन्वय करेगा और उनका अनुवीक्षण करेगा।
- (9) देश में परती भूमि के विकास के लिये अपेक्षित अन्य सभी उपाय करेगा।

मंडेश प्रमाण, मर्चिव।

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
(Department of Environment, Forests and Wildlife)
RESOLUTION

New Delhi, the 11th June, 1990

No. 1-4-90/MM-1.—By Resolution No. 7-22/85-FRY(P) dated 7th May, 1985, the National Wastelands Development Board was established. Vide Resolution No. 1-8/89-TMA dated 9-4-90, it was decided that the Board will adopt a mission approach for enlisting peoples' participation, harnessing science and technology and achieving the necessary inter-disciplinary coordination in the planning and implementation of the Wastelands Development Programme.

2. Further, the following changes are made in the composition and the role and functions of the National Wastelands Development Board with immediate effect.

COMPOSITION**A. Ex-officio-Members :**

- (1) Union Minister for Environment &—Chairman
Forests
- (2) Union Minister of State for Environment & Forests —Vice-Chairman
- (3) Member, Planning Commission, in —Member charge of Environment.
- (4-8) Secretaries to the Govt. of India in the Departments of :
—Agriculture & Co-operation —Member.
Rural Development —Member.
—Agricultural Research & Education —Member
Expenditure —Member
(Finance)
—Science & Technology —Member
- (9) Member-Secretary, National Land Use and Conservation Board.
- (10) Inspector General of Forests, Govt. —Member of India.
- (11) Chairman, National Bank of Agriculture and Rural Development.

B. Nominated Members :

- (12-13) Members of Parliament (one each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha) —Member
- (14-18) Representatives (not exceeding five) of Voluntary Agencies Cooperative —Member Institutions, etc. concerned with wastelands development and related activities (to be nominated each year by the Chairman)
- (19-21) Chief Secretaries of three States (to be nominated each year by the Chairman) —Member.
Member Secretary
- (22) Secretary (Environment & Forests) —Member-Secretary

ROLE AND FUNCTIONS:

The National Wastelands Development Board will be mainly responsible for the Wastelands Development programme aimed at checking land degradation and putting wastelands in the country to sustainable use, increasing biomass availability, especially fuelwood, fodder and forest produce, and storing the ecological balance. The Board will adopt a mission approach for enlisting peoples' participation, harnessing science and technology and achieving inter-disciplinary coordination in the planning and implementa-

tion of the Wastelands Development Programme To this end, it will :

- (i) Formulate, in collaboration with the National Land Use and Conservation Board, a perspective plan for the management/development of the wastelands in the country in a sustainable manner.
- (ii) Identify wastelands, create a reliable data base and collaborate with the concerned Central and State Departments/Agencies, Local Bodies, Voluntary Agencies and other Non-government Organisations to mobilise the resources and support required for the Wastelands Development Programme.
- (iii) Evolve mechanisms for integrated development of wastelands through systematic planning and implementation, in a cost effective manner, specially to meet the needs of the people in the rural areas in respect of fuelwood, fodder and forest produce.
- (iv) Restore, through natural regeneration for appropriate intervention, the forest cover in the country for ecological security and meet the fuelwood, fodder and other needs of the rural communities.
- (v) Raise fuelwood, fodder and timber on non-forest and private wastelands in order to reduce the pressure on the forest areas and to meet the needs of industry and market.
- (vi) Sponsor research and extension of research findings to disseminate new and appropriate technologies for wastelands development.
- (vii) Create general awareness and help foster a people's movement for the Wastelands Development programme with the assistance of Voluntary Agencies, Non-Government Organisations, Panchayati Raj Institutions and others, and promote participatory and sustainable management of community public lands and other similar degraded common property resources.
- (viii) Coordinate and monitor the Action plans for activities related to wastelands development, afforestation, tree planting, soil and moisture conservation, etc., in order to upgrade land quality in a systematic and cost effective manner.
- (ix) Undertake all other measures necessary for promoting wastelands development in the country.

MAHESH PRASAD, Secy.

